शिक्षा-प्रणाली में परिवर्तन

1134. **श्री शिव चरण सिंह :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश की शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने का विचार रखती है; यदि हां, तो प्रस्तावित परिवर्तन क्या-क्या हैं, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि हमारी शिक्षा नीति ने बेरोजगारी को बढ़ावा दिया है ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; यदि नहीं, तो शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या हमारी शिक्षा नीति में ऐसे विषयों को भी सम्मिलित किया जायेगा जिनसे श्रम के प्रति आदर का भाव उत्पन्न हो सके ; और

(घ) क्या लार्ड मैकाले की पुस्तकीय ज्ञान और शासन-सेवा पर आधारित शिक्षा प्रणाली को बदले जाने का प्रस्ताव है ; और यदि हां, तो कब तक?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति (रा०शि०नी०) 1986 के आधार पर निर्मित तथा इसके द्वारा दिशा-निर्देशित है । सरकार का यह अभिमत है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (रा०शि०नी०), 1986 समय की कसौटी पर खरी उतरी है । शिक्षा प्रणाली के संपूर्ण क्षेत्र की गहन समीक्षा पर आधारित तथा राष्ट्रीय जनमत के आधार पर निर्मित इस दिशा नीति में शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्रों के विकास को दिशा-निर्देशित करने के लिये एक वृहत ढांचा है । यह ढांचा आज भी प्रासंगिक है । तथापि गत कुछ वर्षों में हुई प्रगति तथा नीति के कार्यान्वयन में प्राप्त अनुभव के कारण इसमें कुछ संशोधन करना आवश्यक हो गया था । इन संशोधनों को 7 मई, 1992 को सभा पटल पर रख दिया गया था ।

यह कहना सही नहीं है कि शिक्षा नीति से बेरोजगारी बढ़ी है । रोजगार में वृद्धि पूर्णतया अर्थव्यवस्था के विकास पर निर्भर है । शिक्षा किसी भी रूप में रोजगार सृजित नहीं करती है । शिक्षा अर्थव्यवस्था के भिन्न-भिन्न स्तरों के लिये जन-शक्ति का विकास करती है । 1992 में यथा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में व्यक्तिगत रोजगार की संभावना में वृद्धि करने के उद्देश्य से व्यावसायिक शिक्षा पर पहले ही पर्याप्त बल दिया गया है । अध्ययन प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में कार्य अनुभव प्राप्त करने पर भी बल दिया गया है। सामाजिक और नैतिक मूल्य सृजित करने के लिये शिक्षा को एक सशक्त माध्यम बनाने हेतु पाठ्यचर्या को पुनः अभिकल्पित करने की आवश्यकता नीति में स्वीकार की गई है । इस प्रकार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में श्रम की श्रेष्ठता की भावना पैदा करने वाले रोजगारोन्मुख शिक्षा नीति के सभी संभावित पहलुओं को पहले से ही शामिल किया गया है ।

उपलब्ध सूचना के अनुसार 31-12 1991 तक शिक्षित (हाई स्कूल और इससे ऊपर) नौकरी ढूंढने वाले व्यक्तियों की संख्या बेरोजगारी के मौजूदा रजिस्टरों में 2.24 करोड़ थी ।

Criteria for opening Kendriya Vidyalayas

1135. SHRI SHIV CHARAN SINGH: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what are the criteria for opening Kendriya Vidyalayas;

(b) what is the number of Kendriya Vidyalayas as well as students in Rajasthan; and